भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या4998
दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ

ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना

†4998. श्री संजय उत्तमराव देशमुखः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र में कितने डाकघरों और ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध हैं और उनका प्रतिशत कितना है;
(ख) सरकार द्वारा पंचायत संस्थाओं और कार्यालयों को डिजिटल बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के संबंध में आवंटित वार्षिक बजट और अंतिम व्यय कितना है;
(घ) ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना में उपलब्धियों की स्थिति क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा महाराष्ट्र के वाशिम-यवतमाल सांस्कृतिक क्षेत्रों के सभी ग्राम पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए तत्काल क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) पंचायत राज्य का विषय है, इसलिए ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए कंप्यूटर उपलब्ध कराना मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। तथापि, 01.04.2022 से 31.03.2026 तक कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा सीमित पैमाने पर अनुमोदित कंप्यूटर प्रदान करके जीपी के कामकाज में सहायता करने की दिशा में पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा किया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य द्वारा अपनी वार्षिक कार्य योजना में दी गई जानकारी के अनुसार, 27,917 ग्राम पंचायतों (जीपी) में से 27,006 (96.73%) में कंप्यूटर लगे हैं।

दूरसंचार विभाग द्वारा भारतनेट परियोजना को देश भर की सभी ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। भारतनेट यूएनएमएस डैशबोर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारतनेट परियोजना के तहत 27,917 ग्राम पंचायतों में से 24,778 (88.75%) को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है।

इसके अलावा, डाक विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र सर्किल के सभी 2,224 डाकघरों में कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है, जिससे 100% कवरेज प्राप्त हो गया है।

(ख) डिजिटल इंडिया पहल के तहत, मंत्रालय ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर

रहा है, जिसने जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, दक्षता और शासन को काफी हद तक बढ़ाया है। ई-पंचायत एमएमपी के एक हिस्से के रूप में विकसित की गई ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन ने पंचायत स्तर पर डिजिटल योजना, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान की है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ ई-ग्रामस्वराज का एकीकरण विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाता है, जिससे निर्बाध निधि प्रवाह सुनिश्चित होता है और देरी कम होती है। वित्त वर्ष 2024-25 में, 2.55 लाख ग्राम पंचायतों ने अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (जीपीडीपी) अपलोड कीं, और ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से ₹58,000 करोड़ से अधिक हस्तांतरित किए गए। चालू वित्त वर्ष के दौरान ई-ग्रामस्वराज को राज्यवार अपनाने की जानकारी **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने पंचायत खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ग्रामस्वराज को सरकारी ई -मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ एकीकृत किया है। यह एकीकरण पंचायतों को ई-ग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म के द्वारा जीईएम के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करने की सुविधा देता है, जिससे "वोकल फॉर लोकल" पहल को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा विकसित की गई मेरी पंचायत जैसे एप्लीकेशनों ने पंचायत में नियोजन, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति की जानकारी जनता तक पहुँचाकर पंचायत शासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। इसी तरह, पंचायत निर्णय एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता लाना और बेहतर प्रबंधन करना है।

इसके अलावा, पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन के ऑनलाइन ऑडिट के लिए एक एप्लिकेशन 'ऑडिटऑनलाइन' विकसित किया गया है। अप्रैल 2020 में पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग की निधि के उपयोग के पारदर्शी लेखापरीक्षण के लिए ऑडिटऑनलाइन की शुरुआत की गई। लेखापरीक्षा वर्ष 2022-23 के लिए, 2.58 लाख लेखापरीक्षा योजनाएँ बनाई गई हैं और पीआरआई द्वारा 2.57 लाख लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई हैं।

इसके अलावा, डिजिटल इंडिया के विजन को प्राप्त करने के लिए, दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु चरणबद्ध तरीके से भारतनेट परियोजना को लागू किया जा रहा है। अब तक, कुल 2.68 लाख ग्राम पंचायतों/पारंपरिक स्थानीय निकायों (TLB) में से 2.18 लाख GP/TLB को भारतनेट परियोजना के तहत हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करने हेतु सेवा के लिए तैयार किया गया है। डिजिटल कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए, भारतनेट चरण- । और चरण- ॥ के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन और शेष ग्राम पंचायतों में नेटवर्क के निर्माण के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को दिनांक 04.08.2023 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(ग) ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत ई-पंचायत एप्लीकेशनों के रखरखाव के लिए केंद्रीय स्तर पर सहायता हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगम (एनआईसीएसआई) को धनराशि प्रदान की जा रही है। पिछले तीन वर्षों में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना पर वर्षवार वार्षिक व्यय निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	बजट अनुमान (बी.ई.)	संशोधित अनुमान (आर.ई.)	वास्तविक व्यय
2021-22	20	11.71	11.71
2022-23	20	15	15
2023-24	20	16.28	16.03

(घ) ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत सभी ग्राम पंचायतों को ई-ग्रामस्वराज और अन्य एप्लीकेशनों की विभिन्न कार्यक्षमताओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है। आज तक, 2.55 लाख ग्राम पंचायत (जीपी), 5,952 ब्लॉक पंचायत और 546 जिला पंचायतों ने 2024-25 के

लिए अपनी विकास योजनाएं तैयार की हैं और उन्हें ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन पर अपलोड किया है। इसके अलावा, 2.56 लाख जीपी ने चालू वर्ष 2024-25 में लेखांकन के उद्देश्य से ई-ग्रामस्वराज को अपनाया है, जिनमें से 2.44 लाख जीपी ने ई-ग्राम स्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान शुरू किया है।

(ङ) मंत्रालय राज्यों को ई-ग्रामस्वराज एप्लीकेशन अपनाने के लिए वर्चुअल और फिजिकल प्रशिक्षण और सक्षमता के माध्यम से लगातार राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। प्रगति की समीक्षा के लिए नियमित रूप से समीक्षा बैठकें, कार्यशालाएँ, हैंड-होल्डिंग सत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंस और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्यों का दौरा किया जाता है। एक राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) भी इस परियोजना के कार्यान्वयन का समन्वय/सुविधा प्रदान करती है। महाराष्ट्र सहित सभी राज्य अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ई-पंचायत एमएमपी को लागू करने के प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा, वाशिम और यवतमाल जिला पंचायतों के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों को ई-ग्राम स्वराज पर ऑनबोर्ड कर लिया गया है।

***

अनुलग्नक-I

'ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना' के संबंध में दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4998 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पंचायत स्तर पर ई-ग्रामस्वराज को राज्यवार अपनाना

क्र.सं.	ग्राम पंचायतों एवं समकक्षों की कुल संख्या	शामिल ग्राम पंचायत	ऑनलाइन भुगतान के साथ ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों की कुल संख्या	शामिल ब्लॉक पंचायत	ऑनलाइन भुगतान के साथ ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतों एवं समकक्षों की कुल संख्या	शामिल जिला पंचायत	ऑनलाइन भुगतान के साथ जिला पंचायतें
1	13328	13296	12970	660	660	642	13	13	13
2	2108	2106	222	0	0	0	27	25	8
3	2662	2197	2176	191	191	189	30	29	27
4	8054	8054	8045	534	534	530	38	38	38
5	11596	11594	11516	146	146	146	27	27	27
6	191	190	93	0	0	0	2	2	2
7	14656	14599	13890	248	248	248	33	33	33
8	6226	6222	5914	143	143	134	22	22	22
9	3615	3614	3540	81	81	81	12	12	12
10	4345	4345	4329	264	264	262	24	24	24
11	5954	5954	5937	238	232	126	31	31	28
12	941	941	941	152	152	152	14	14	14
13	23011	23009	22980	313	313	310	52	52	52
14	27917	27894	26737	351	351	307	34	34	34
15	3180	161	123	0	0	0	12	6	4
16	6817	0	0	2241	0	0	3	3	0
17	842	842	832	0	0	0	0	0	0
18	1289	186	0	0	0	0	0	0	0
19	6794	6794	6793	314	314	314	30	30	30
20	13237	13222	9775	152	151	114	22	22	19
21	11211	11207	10837	361	353	351	33	33	33
22	199	199	195	0	0	0	6	6	6

23	12525	12525	12519	388	388	388	36	36	36
24	12991	12768	12636	572	540	508	32	32	32
25	1194	1185	1174	75	75	75	9	9	9
26	7795	7794	7743	95	95	95	13	13	13
27	57691	57691	57609	826	826	818	75	75	75
28	3339	3339	3338	345	345	345	22	21	21
कुल	**263708**	**251928**	**242864**	**8690**	**6402**	**6135**	**652**	**642**	**612**